Gyanvividha, Vol.-3; Issue-3 (July-September) 2026 : PP-100-102

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों की अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध-पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-6.125
Vol.-3; Issue-3 (July-Sept.) 2026
Page No.- 100-102
©2026 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

डॉ. डेकेष्वरी

अतिथि सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी.

Corresponding Author :

डॉ. डेकेष्वरी

अतिथि सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी.

गिग श्रमिक की समस्याएँ, चुनौतियाँ एवं सुझाव : एक अध्ययन

बीज शब्द : आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पारंपरिक, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण।

सारांश : डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तीव्र विस्तार ने रोजगार के पारंपरिक स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप गिग अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, जिसमें श्रमिक स्थायी रोजगार के बजाय अल्पकालिक, कार्य–आधारित या मांग–आधारित सेवाएँ प्रदान करते हैं। ऑनलाइन कैब सेवा, खाद्य एवं किराना डिलीवरी, ई–कॉमर्स, घरेलू सेवाएँ, फ्रीलांसिंग तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म गिग रोजगार के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में बढ़ते डिजिटलीकरण, बेरोजगारी, शहरीकरण और लचीले रोजगार की मांग के कारण गिग श्रमिकों की संख्या एवं आर्थिक महत्व निरंतर बढ़ रहा है।

गिग अर्थव्यवस्था एक ओर युवाओं एवं अन्य श्रमिकों को रोजगार और आय के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराती है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े श्रमिकों को आय की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कार्य के लंबे घंटे, प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता, रोजगार की अस्थिरता और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी जोखिमों जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए गिग श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों और सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन वर्तमान समय में महत्वपूर्ण हो गया है।

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आधारित सेवाओं के विस्तार ने रोजगार के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप गिग अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत श्रमिक स्थायी रोजगार के स्थान पर कार्य–आधारित अथवा अल्पकालिक अनुबंधों के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करते हैं। भारत में भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आधारित कंपनियों के विस्तार के साथ गिग श्रमिकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। खाद्य वितरण, कैब सेवाएँ, ई–कॉमर्स डिलीवरी, फ्रीलांसिंग, घरेलू सेवाएँ तथा डिजिटल पेशेवर सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में लाखों लोग गिग श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। यह व्यवस्था रोजगार के नए अवसर, कार्य की लचीलापन तथा आय अर्जित करने के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराती है। यद्यपि गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार के नए आयाम स्थापित किए हैं, तथापि इससे जुड़े श्रमिक अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। नियमित रोजगार का अभाव, आय की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित होना, स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन जैसी सुविधाओं का अभाव, कार्य के निश्चित घंटे न होना, एल्गोरिदम आधारित कार्य प्रबंधन, प्लेटफ़ॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता तथा नौकरी की सुरक्षा का अभाव उनकी प्रमुख समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के अधिकारों की सीमित सुरक्षा, सामूहिक सौदेबाजी की कमी तथा कार्यस्थल पर जोखिम भी उनकी स्थिति को अधिक जटिल बनाते हैं।

इन परिस्थितियों में गिग श्रमिकों की समस्याओं एवं चुनौतियों का समग्र अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यवहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य गिग श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों, आय, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों तथा उनके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना है। साथ ही, अध्ययन के माध्यम से ऐसे सुझाव प्रस्तुत किए जाएँगे, जिनके आधार पर सरकार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कंपनियाँ तथा अन्य संबंधित हितधारक गिग श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित, न्यायसंगत एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित कर सकें। यह अध्ययन श्रम बाज़ार में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को समझने तथा समावेशी एवं सतत रोजगार नीति के निर्माण में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

गिग श्रमिक कौन होते हैं ? : गिग श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो किसी एक नियोक्ता के अधीन स्थायी रूप से कार्य करने के बजाय अल्पकालिक, अस्थायी अथवा कार्य–आधारित सेवाएँ प्रदान करते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के साथ गिग कार्य का विस्तार तेजी से हुआ है। वर्तमान में खाद्य वितरण, टैक्सी सेवाएँ, ई–कॉमर्स डिलीवरी, फ्रीलांस लेखन, ग्राफिक डिज़ाइन, सॉफ़्टवेयर विकास, ऑनलाइन शिक्षण तथा घरेलू सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में गिग श्रमिक कार्यरत हैं। इस प्रकार के कार्य में समय और कार्यस्थल की अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन होता है, जिससे श्रमिक अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। दूसरी ओर, अधिकांश गिग श्रमिकों को नियमित वेतन, नौकरी की सुरक्षा, भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, सवेतन अवकाश तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण उनकी आजीविका अपेक्षाकृत असुरक्षित बनी रहती है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार के साथ इन श्रमिकों के अधिकारों, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों तथा सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसलिए गिग श्रमिक आधुनिक श्रम बाज़ार का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियों एवं कानूनी प्रावधानों का विकास समय की आवश्यकता है।

भारत में गिग श्रमिक : भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ गिग कार्य का तेजी से विकास हुआ है। भोजन वितरण, टैक्सी सेवा, ई–कॉमर्स डिलीवरी, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन शिक्षण तथा आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग गिग श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।

गिग श्रमिकों की प्रमुख विशेषताएँ

- स्थायी रोजगार के बजाय कार्य–आधारित रोजगार।
- कार्य के घंटे अपेक्षाकृत लचीले होते हैं।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या मोबाइल एप के माध्यम से कार्य प्राप्त करते हैं।
- प्रति कार्य, प्रति डिलीवरी या प्रति परियोजना के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं।
- अधिकांश मामलों में कर्मचारी के बजाय स्वतंत्र ठेकेदार माने जाते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य कर्मचारी लाभ सीमित या अनुपलब्ध होते हैं।
- गिग श्रमिकों के उदाहरण
- फूड डिलीवरी एजेंट
- ऑनलाइन टैक्सी चालक
- ई–कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर
- फ्रीलांस लेखक एवं ग्राफिक डिज़ाइनर
- ऑनलाइन शिक्षक एवं प्रशिक्षक
- ऐप आधारित घरेलू सेवा प्रदाता
- गिग श्रमिकों के लाभ
- कार्य करने के समय में लचीलापन।
- अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर।
- कम निवेश में रोजगार उपलब्ध।
- युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए अवसर।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं उद्यमिता को बढ़ावा।
- गिग श्रमिकों की समस्याएँ
- रोजगार की स्थिरता का अभाव।
- सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा, भविष्य निधि आदि) का अभाव।
- आय में अनिश्चितता।
- कार्य के दौरान दुर्घटना एवं स्वास्थ्य संबंधी जोखिम।
- एल्गोरिदम आधारित मूल्यांकन एवं कार्य आवंटन की पारदर्शिता की कमी।
- श्रमिक अधिकारों एवं सामूहिक सौदेबाजी के सीमित अवसर।

वर्तमान में गिग श्रमिकों की स्थिति : वर्तमान समय में भारत में गिग अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है। ऑनलाइन टैक्सी, फूड डिलीवरी, ई–कॉमर्स, घरेलू सेवाएँ, फ्रीलांसिंग तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आधारित कार्यों के कारण गिग श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये श्रमिक शहरी एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुके हैं, किंतु इनके सामने रोजगार सुरक्षा, आय की स्थिरता तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ :

- आय की अनिश्चितता एवं असमान भुगतान।
- सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन का सीमित कवरेज।
- स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का अपर्याप्त प्रावधान।
- कार्य समय अधिक होने के बावजूद आय में स्थिरता का अभाव।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के एल्गोरिदम एवं रेटिंग प्रणाली पर अत्यधिक निर्भरता।
- श्रमिक संगठनों एवं सामूहिक सौदेबाजी की सीमित क्षमता।

गिग श्रमिकों के लिए सुझाव :

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी विस्तार किया जाए।
- दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य बनाया जाए।
- न्यूनतम पारिश्रमिक एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर पारदर्शी कार्य एवं भुगतान व्यवस्था विकसित की जाए।
- कौशल विकास एवं डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।
- गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रभावी कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

निष्कर्ष : गिग श्रमिक आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं और सेवा क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि रोजगार की अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षा का अभाव तथा आय की अनिश्चितता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कंपनियाँ तथा अन्य हितधारक मिलकर ऐसी नीतियाँ विकसित करें, जिनसे गिग श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं टिकाऊ कार्य वातावरण प्राप्त हो सके।

संदर्भ :

1. NITI AYOG (2022). *India's Booming Gig and Platform Economy: Perspectives and Recommendations on the Future of Work*. Government of India, New Delhi.
2. International Labour Organization (ILO). (2021). *World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work*. Geneva: ILO.
3. International Labour Organization (ILO). (2024). *Realizing Decent Work in the Platform Economy*. International Labour Conference, Geneva.
4. Ministry of Labour and Employment, Government of India. *Annual Report*. Government of India, New Delhi.
5. NITI Aayog. (2022). *India's Gig and Platform Economy: A Policy Perspective*. Government of India, New Delhi.
6. International Labour Organization. (2021). *Working on a Better Future: Platform Work and the Changing Nature of Employment*. Geneva: ILO.
7. Kalleberg, A. L. (2009). "Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition." *American Sociological Review*, 74(1), 1–22.
8. De Stefano, V. (2016). "The Rise of the Just-in-Time Workforce: On-Demand Work, Crowdwork, and Labour Protection in the Gig-Economy." *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 471–504.
9. International Labour Organization. *World Employment and Social Outlook: Trends*. Geneva: ILO.
10. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. *Periodic Labour Force Survey (PLFS)*. New Delhi.
11. Reserve Bank of India. *Report on Currency and Finance / Annual Report*. Mumbai: RBI.
12. Government of India. *Economic Survey of India*. Ministry of Finance, New Delhi.
13. OECD. (2019). *Policy Responses to New Forms of Work*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

•